कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) जी, नहीं । कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० की भूमिगत खानों द्वारा कोयले का उत्पादन वर्ष 1974-75 में 64.30 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 1992-93 में 70.36 मिलियन टन किया गया ।

(ग) और (घ) यद्यपि भारत में अनुसंधान संस्थानों द्वारा किसी विशेष खनन प्रौद्योगिकी को विकसित नहीं किया गया है, अनेक प्रमुख कोयला उत्पादक देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी, यू० के०, पोलैंड तथा रूस से सहायता लेकर 1974—93 की अवधि के दौरान कई नई भूमिगत खनन प्रौद्योगिकियों को आरंभ किया गया है । इनमें से कुछ प्रौद्योगिकियां निम्न है : पावर स्पोर्ट उपकरण के इस्तेमाल से यांत्रिकृत लांगवाल माइनिंग तथा सब-लेबल केविंग; गैलरी ब्लास्टिंग पद्धति; साइड डिस्चार्ज लोडर (एस० डी० एल०) तथा लोड हाल डम्पर्स (एल० एच० डी०) के इस्तेमाल द्वारा यांत्रिकृत बोर्ड तथा पिल्लर; डिसैंडिंग शील्ड माइनिंग, आदि ।

(ङ) कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० के अधिकारियों का एक तकनीकी दल चीन की यात्रा पर गया है, ताकि कठिन तथा विस्तृत सैंडस्टोन स्थितियों में, जैसी कि कुछ हमारी खानों में भी व्याप्त हैं, भूमिगत लांगवाल मुहानों में छत के प्रबंधन संबंधी चीन की प्रक्रियाओं का गहन अध्ययन किया जा सके ।

(च) इसमें अन्तर्ग्रस्त लागत तथा प्राप्त की जाने वाली संभावित उत्पादकता का अभी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है ।

Implementation of 'No Work, No Pay' Policy

*271. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some State Governments are implementing the policy of "no work, no pay" in respect of Government, public sector and local self Government employees of such States;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether Government proposes to apply the policy at the national level in the near future; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) and (d) "No work, no pay" is already the general policy of the Government of India also.

कोयले के बढ़ते मूल्यों का असर

*272. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1991 से देश में कोयले की कीमतों में लगभग 48% वृद्धि हुई है और इसके फलस्वरूप बिजली उत्पादन और इस्पात उत्पादन में क्रमश: रू० 1.27 प्रति के०डब्ल्यू०एच० और रू० 61.00 प्रति टन की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि क्रमश: मार्च, 1992 और मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्षों के अंत में देश में कोयला उद्योग ने लाभ कमाया है;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के दौरान कितना-कितना लाभ कमाया गया;

(ङ) क्या इन वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन की लागत में भी कमी आई है, यदि हां, तो प्रतिवर्ष उसमें अनुमानत: कितनी कमी आई है; और

(च) देश में कोयला खनन उद्योग में कुल कितनी पूंजी का निवेश हुआ है तथा इसमें विदेशी पूंजी कितनी है और कर्ज ली गई राशि कितनी है तथा कर्ज पर प्रतिवर्ष कितना ब्याज दिया जाता है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1991 के बाद से कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० द्वारा उत्पादित कोयले की कीमतों में निम्नलिखित वृद्धि प्रभावी की गई है :—

कंपनी	तारीख जब से प्रभावी हुई	औसत कीमत प्रति मि० टन		प्रतिशतता में वृद्धि
		वृद्धि से पूर्व	वृद्धि के बाद	
को०इं०लि०	17-2-93	322*	364	13.04
	19-6-93	364	382	4.9
सिं०को०कं०लि०	17-2-93	388*	434	11.85
	19-6-93	434	452	4.15

(* दिसम्बर, 1991 में निर्धारित की गई कीमतें)

दिसम्बर, 1991 से जून, 1993 तक वृद्धि प्रतिशतता, कोल इंडिया लि० (को०इं० लि०) के मामले में 18.6% और सिंगरेनी